भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.12.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2976 का उत्तर

जम्मू और कश्मीर में रेलवे नेटवर्क

2976. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त विस्तार से स्थानीय समुदायों और व्यवसायों को किस प्रकार लाभ हो रहा है;

(ख) क्या भारतीय रेल द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई बेहतर यात्री सेवाओं और सुविधाओं से निवासियों और पर्यटकों के यात्रा अनुभव में समान रूप से वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों को आकर्षित करके और इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतीय रेल की क्या भूमिका है;

(घ) यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू और कश्मीर में रेल मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना की प्रगति और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना के लिए आवंटित और व्यय किए गए बजट का ब्यौरा क्या है और इसके अनुमोदन से अब तक कितना कार्य पूरा किया गया है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

जम्मू और कश्मीर में रेलवे नेटवर्क के संबंध में दिनांक 20.12.2023 को लोक सभा में श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल, श्री बिद्युत बरन महतो और श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2976 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): जम्मू और कश्मीर में नई लाइन का कार्य उधमपुर - श्रीनगर - बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है । उधमपुर - श्रीनगर - बारामूला रेल लिंक परियोजना के कुल 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर पहले ही चालू किया जा चुका है। कटरा - बानिहाल (111 किलोमीटर) रेलखंड का कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना की प्रत्याशित लागत 37,012/- करोड़ रुपये है, जिसके अंतर्गत मार्च,2023 तक इस परियोजना पर 34,261/- करोड़ का व्यय उपगत किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए 5,310 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

शायद उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना स्वतंत्रता के बाद देश में शुरू की गई सबसे कठिन नई रेल लाइन परियोजना है। यह भूभाग नवोदित हिमालय से होकर गुजरता है, जो भूविज्ञानी अजूबों और कई समस्याओं से भरा है। इस रेलखंड में मुख्यत: सुरंग बनाना अंतर्ग्रस्त है अर्थात कटरा-बानिहाल रेलखंड की 111 किलोमीटर लंबाई में से 97.42 किलोमीटर (अर्थात 87%) सुरंगों में है और सुरंग टी-49 की अधिकतम लंबाई 12.77 किलोमीटर है, जो कि देश की सबसे लंबी परिवहन रेल सुरंग होगी। रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया है। प्रतिष्ठित चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है जिसमें 467 मीटर का तोरण पथ स्पैन है और नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई है। अंजिकड़ के ऊपर भारतीय रेल का पहला केबल पुल बनाया गया है। इसका पुल डेक नदी तल के स्तर से 331 मीटर ऊपर है और इसके मुख्य तोरण की ऊंचाई 193 मीटर है।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित लाइनों का अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है:

i. बारामूला - बानिहाल रेलखंड का दोहरीकरण (135.5 किलोमीटर)
ii. बारामूला - उरी की नई लाइन (50 किलोमीटर)
iii. सोपोर - कुपवाड़ा नई लाइन (33.7 किलोमीटर)
iv. अवंतीपोरा - शोपियां नई लाइन (27.6 किलोमीटर)
v. अनंतनाग - बिजबेहरा - पहलगाम नई लाइन (77.5 किलोमीटर)

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना ने इस क्षेत्र में बहुत अधिक सामाजिक-आर्थिक योगदान दिया है, जहां रोजगार सृजन पर इसका प्रभाव एक उद्देश्यपूर्ण पहलू है। अभी तक इस परियोजना से 553 लाख से अधिक मानव-दिवसों के अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक अन्य उद्देश्यपूर्ण पहलू इस परियोजना के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयास स्वरूप 215 किलोमीटर से अधिक पहुंचमार्ग सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक सुरंग और 320 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है।

इस समय कश्मीर घाटी रेलखंड पर 9 जोड़ी रेलगाड़ियां चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों का यात्रा समय कम हो गया है और यात्रा अनुभव भी बस सेवाओं की तुलना में अधिक आरामदायक हो गया है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बड़े पुनर्विकास द्वारा यात्री सेवाओं और सुविधाओं में सुधार लाया जा रहा है। यात्रियों के यात्रा अनुभव का संवर्धन करने के लिए, कश्मीर घाटी में चलाई जा रही एक विशेष रेलगाड़ी में एक विस्टाडोम कोच लगा हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित एक गेस्ट हाउस उपलब्ध है। रेलगाड़ियों में यात्रियों को रसोई यान/मिनीपेंट्री, ट्रेन साइडवेंडिंग और मार्गवर्ती रेलवे स्टेशनों पर स्थैतिक इकाइयों द्वारा खानपान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग सेवाओं द्वारा अपनी पसंद का भोजन मंगाने की सुविधा भी मौजूद है जो मार्गवर्ती बड़े रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।

रेल आधारित पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य ऐतिहासिक स्थानों को दिखाने के उद्देश्य से, नवंबर 2021 में भारतीय रेल द्वारा 'भारत गौरव ट्रेन' नीति जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत थीम आधारित पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इस नीति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को भारत गौरव पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियां चलाने के लिए थीम/यात्रा कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसमें बाजार की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य सहित भारत के किसी भी भाग के पर्यटक सर्किट शामिल हो सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना में पर्याप्त संरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सभी सुरंगों को यांत्रिक संवातन तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

सभी सुरंगों में आग की संभावित घटनाओं का तत्परतापूर्वक निवारण करने और उन काबू पाने के लिए पानी के बंबों और अग्निशामक यंत्रों से युक्त अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध कराई गई हैं। सभी बचाव सुरंगों और सुरंगों में आने-जाने के मार्गों के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है।

रेलवे द्वारा रेल मार्गों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें संरक्षा अभियानों, संरक्षा ऑडिट, संरक्षा निरीक्षण, सड़क उपयोगकर्ता की काउंसलिंग, पर्चे बांटना, नुक्कड़ नाटक करवाना, संरक्षा सेमिनार और रेल संरक्षा के बारे में जागरूकता के संबंध में जनता के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजना शामिल हैं। बारामुला और बानिहाल के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों का रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में पूर्णत:/अंशत: स्थित अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन इस प्रकार है:-

अवधि	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1044 करोड़ रु./वर्ष	-
2023-24	6003 करोड़ रु.	5 गुना से अधिक

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत का हिस्सा जमा करवाना, अतिलंघनकारीजनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिकस्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिकपरिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु दृष्टिकोण से परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

सरकार द्वारा रेल परियोजनाओं के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें (i) मंत्रालय में गति शक्ति निदेशालय और फील्ड गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की वरीयता निर्धारण (iii) पर्याप्त धन आबंटन (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की गहन निगरानी (vi) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव स्वीकृति और परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से अनुवर्ती कार्रवाई करना। जम्मू और कश्मीर में रेल लाइन के विस्तार से परिवहन और संपर्क-व्यवस्था में सुधार आने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने और वस्तुओं एवं सेवाओं का संचलन साध्य होने से स्थानीय समुदाय और व्यवसाय लाभान्वित हो रहे हैं। यह इस क्षेत्र के लिए एक सुस्पष्ट प्रगति है।

*****